भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 919

बुधवार, 07 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग (एलपीआई)

919. श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर:
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे:
श्री नारणभाई काछड़िया:
श्री दिलीप शइकीया:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री देवजी पटेल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश की वर्तमान लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (एलपीआई) रैंकिग क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश की एलपीआई रैंकिंग सुधारने के लिए कोई कार्ययोजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में लॉजिस्टिक्स कुशलता सुधारने के लिए कौन-से नवीन कदम उठाए गए है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क): विश्व बैंक की 'लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिग (2023): कनेक्टिंग टु कम्पीट 2023' के अनुसार, 139 देशों में भारत का 38वां स्थान है। भारत की रैंक में वर्ष 2018 के 44वें पायदान से छ: पायदान का सुधार हुआ है तथा वर्ष 2014 के 54वें पायदान से सोलह पायदान बेहतर हुई है।

(ख) और (ग): एक अंतर-मंत्रालयी डेडिकेटिड टीम का गठन किया गया है जिसमें हितधारक मंत्रालय/विभाग शामिल हैं। ये हितधारक मंत्रालय/विभाग लक्षित कार्य योजनाओं पर फोकस करते हैं जिसमें लॉजिस्टिक्स के कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए सभी छ: एलपीआई मानदंडों अर्थात सीमा शुल्क, अवसंरचना, ईज़ ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट, लॉजिस्टिक सेवाओं की गुणवत्ता, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग तथा समयबद्धता में सुधार के लिए आवश्यक कार्य समाहित है। इसके अलावा, राष्ट्रीय व्यापार सहायता समिति (एनसीटीएफ) में तीन-स्तरीय संरचना है जिसमें एक राष्ट्रीय व्यापार सहायता समिति, एक संचालन समिति और फोकस्ड कार्य समूह

(आउटरीच, विधायी मामले, टाइम रिलीज़ स्टडी, अवसंरचना उन्नयन, पीजीए विनियम और प्रक्रिया) का गठन शामिल है। संबंधित एनटीएफएपी 2020-23 में, अवसंरचना उन्नयन संबंधी कार्य समूह के तहत 27 कार्य बिन्दुओं को चिह्नित किया गया है।

(घ) : माननीय प्रधानमंत्री ने लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी के लिए 13 अक्टूबर 2021 को मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी संबंधी पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टरप्लान तथा 17 सितंबर, 2022 को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की घोषणा की थी। डिजिटल सुधार, जैसे ईज़ ऑफ डूइं ग बिजनेस के लिए यू नीफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) और लॉजिस्टिक्स डाटा बैंक, जिसमें 100 प्रतिशत कंटेनराज्ड एग्जिम कार्गो का डिजिटल ट्रैक और ट्रेस है, वर्तमान में प्रचालनरत है। इसके अलावा, संबंधित मंत्रालयों ने विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- रेल मंत्रालय द्वारा रेल की पटरियों के विद्युतीकरण का विस्तार;
- भारतीय भू-पत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई) ने कार्यक्रमों के जरिए औसत निर्यात और आयात रिलीज टाइम में कमी की है;
- पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एनएलपी मरीन की शुरूआत की है जो पत्तन संबंधी लॉजिस्टिक प्रचालनों के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा, अन्य प्रमुख पहलें भी की गई हैं जैसे वे-ब्रिजेस का ऑटोमेशन किया जा रहा है।

*****